कुछ करने के लिए ये सोचें कि आप यें कर सकते है।
– अज्ञात

कोरोना विकराल होता वायरस

कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। अमेरिका समेत लगभग हर देश में मेडिकल इंडस्ट्री का जोर निजी बीमारियों के इलाज पर है। पूरे समाज को ध्यान में रखने वाला कम्यूनिटी हेल्थ सिस्टम अस्पतालों के अजेंडा पर ही नहीं है।

अमित शाह।

जिस बात की आशंका थी, वह सच साबित हुई। कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके कारण पूरे विश्व में भयंकर तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। मोटे आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में 81 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं।

आज की तारीख में यह बीमारी चीन के करीबी मुल्कों के अलावा ईरान, इटली और अमेरिका तक पहुंच चुकी है और इसका छिटपुट विस्तार मिडल ईस्ट और यूरोप के कई देशों तक हो चुका है। दक्षिण कोरिया का देगू शहर अभी इस विषाणु को लेकर कमोबेश चीन के वूहान जितनी ही चर्चा में है।

बृहस्पतिवार को इस देश में कोरोना वायरस के कुल 1766 मरीज दर्ज किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार चीन के बाहर कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 25 फरवरी को चीन में 411 नए मामले सामने आए, जबकि अन्य देशों में 427 नए मामलों का पता चला। मौतों के लिहाज से चीन के बाद इस वायरस का सबसे खतरनाक ठिकाना ईरान बन गया है, जहां इसके संक्रमण ने अब तक 19 लोगों की जान ले ली है। एक ईरानी सांसद का दावा है कि अकेले पवित्र शहर कुम में ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

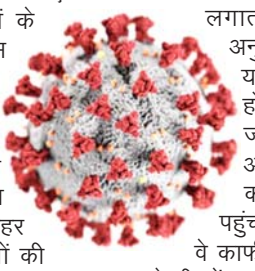

ईरान के स्वास्थ्य उपमंत्री इराज हरिरची ने इस दावे का खंडन किया, हालांकि अगले ही दिन उन्होंने खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा भी की। बताया जा रहा है कि कुम शहर में एक चीनी कंपनी सोलर प्लांट लगा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में चीनी इंजीनियर और मिस्त्री काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार चीन आ–जा रहे थे। अनुमान है कि उन्हीं के जरिए यह वायरस ईरान में आया होगा। यहां हालात आगे और ज्यादा बिगड़ सकते हैं क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कई जरूरी दवाएं ईरान नहीं पहुंच रहीं और जो पहुंच रही हैं, वे काफी महंगी हैं। रही बात बीमारी के ट्रीटमेंट की तो यह मरीज को विटामिन और एंटीबायोटिक देने के अलावा उसके शरीर में लगातार फ्लूइड पहुंचाने तक ही सीमित है। इसकी वैक्सीन या कोई कारगर इलाज अभी नहीं खोजा जा सका है तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वैज्ञानिक इसके स्रोत को लेकर कोई आम राय नहीं बना सके हैं। शुरू में कहा गया कि यह चमगादड़ और सांप से फैला लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। अमेरिका समेत लगभग हर देश में मेडिकल इंडस्ट्री का जोर निजी बीमारियों के इलाज पर है।

पूरे समाज को ध्यान में रखने वाला कम्यूनिटी हेल्थ सिस्टम अस्पतालों के अजेंडा पर ही नहीं है। ऐसे में महामारी फैलने की स्थिति में इससे कैसे निपटा जाएगा, यह बड़ा सवाल है। भारत को भी इसका जवाब समय रहते खोज लेना चाहिए।

अनंत संभावनाएं

अशोक वोहरा। शून्य और एक के बीच अनंत संभावनाएं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वव्यापी भव्य चेतना किसी भी परिवर्तन से परे है। यह संपूर्ण संगीत के मौलिक स्वरों की तरह उजागर होती है जैसे समुद्र की सतह पर बुलबुले उभरते हैं। एक बार हम मौलिक स्वरों को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए विविधता में भी समानता देखना संभव हो जाता है और किसी भी परिवर्तन से परे कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता है। हालांकि प्रत्येक नए परिवर्तन में पुराना अपरिहार्य मौजूद रहता है। एक बार मन अंदर झांक लेता है और अपने आसपास मौजूद संगीत के मौलिक स्वरों को अनुभव करने लगता है, तब परिवर्तन जरूरत से ज्यादा दिखाई देता है– स्थायित्व प्रमुख हो जाता है। और यह मन की एक स्थिति है जो 'यह है कि वह है' को शांत करता है।

धर्म-दर्शन

संपादकीय

ठंडी करें आग

इस समय जरूरी यह है कि सभी पार्टियों के नेता, सभी धर्मों के अग्रणी लोग और देश के बुद्धिजीवी इस सांप्रदायिक आग को ठंडी करें। दिल्ली में जो हुआ, सो हुआ। यह देश में कहीं और न हो। एक सत्य दोनों पक्षों को समझ लेना चाहिए। जो इस नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें भी और जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी। जो विरोध कर रहे हैं, यदि उन पर हिंसा का बिल्ला चिपक गया तो उनके विरोध को जनता की जो व्यापक सहानुभूति मिल रही है, वह खत्म होती चली जाएगी। और इस विरोध को टक्कर देने के नाम पर जो उत्साहीलाल अपने नेताओं की खुशामद में लगे हैं, वे काफी बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। संतोष की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दंगाग्रस्त बस्तियों में गए और परेशान लोगों से सीधे संवाद किया। इससे लोगों को कुछ राहत मिली। डोभाल तो अफसर हैं लेकिन नेताओं को कोई शर्म क्यों नहीं आई? लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध जिस क्रूरता का परिचय दिया है, वह हमें इंसान नहीं, जानवर बना देती है। दिल्ली शहर में अगर यह हो सकता है तो हमारी 73 साल की आजादी, लोकतंत्र और संस्कृति के माथे पर लगा यह काला टीका है। ऐसा नहीं है कि हादसे पर सभी संवैधानिक संस्थाएं चुप लगा गई हैं। प्रधानमंत्री ने भी शांति की अपील की है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय राय दिल्ली हाईकोर्ट की रही। जस्टिस एस. मुरलीधर की हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए, जिन्होंने दो–टूक शब्दों में पुलिस और प्रशासन को डांट लगाई है। उन्होंने सरकारी वकील को फटकारते हुए पूछा है कि क्या दिल्ली में 1984 के कांड को दोहराना चाहते हैं?

देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के विरोध–प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। लेकिन समझ में नहीं आता कि इन दोनों प्रावधानों के समर्थन में सभाएं और प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी?

लोकतंत्र की नाकामी हैं दंगे

वेदप्रताप वैदिक।

दिल्ली में इस तरह के दंगे की कल्पना ही हमारे लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए काफी है। 1947 में विभाजन से जुड़े उपद्रव को छोड़ दें तो 1984 में सिखों के विरुद्ध रक्तपात की ज्वाला जरूर भड़की थी लेकिन वह एकतरफा थी और उसके पीछे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या थी। लेकिन पिछले चार–पांच दिनों में जो दंगे भड़के हैं, इनके पीछे कारण क्या है? दिल्ली का यह उत्तर–पूर्वी क्षेत्र अपनी शांतिप्रियता और मेल–जोल के लिए जाना जाता है। पिछले 36 सालों में राजधानी में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि दो संप्रदायों के लोग हर्बे–हथियार लेकर एक–दूसरे पर टूट पड़े हों।

सत्याग्रह की खुशबू: जहां तक एनसीआर और सीएए का सवाल है, उनका विरोध दिल्ली में ही नहीं, देश के कई शहरों में हो रहा है लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें कहीं से भी नहीं आ रही हैं। जितने शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से ये धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे गांधीजी के सत्याग्रह की खुशबू आ रही है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के विरोध–प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। लेकिन समझ में नहीं आता कि इन दोनों प्रावधानों के समर्थन में सभाएं और प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? संसद ने बहुमत से इस संशोधन को पारित किया है।

सरकार अब तक उसी पर डटी हुई है। उसके समर्थन में कुछ नेताओं को अत्यंत उत्तेजक भाषण देने की जरूरत क्या थी? यदि उसका कोई समर्थन करना चाहे तो जरूर करे लेकिन उसका विरोध करने वालों को गद्दार कहना, उनको गोली मारने का नारा लगवाना, उनको हत्यारा और बलात्कारी घोषित करवाना आखिर क्या है? ये जो दंगे हुए हैं, कहीं वे इन्हीं कारनामों का अंजाम तो नहीं हैं?

आंदोलन हिंदू–मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहा था, उसे सांप्रदायिक रूप देने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर वे नेता गंभीरता से विचार करें, जिनके शिष्यों ने उग्रता में अपना आपा खो दिया था। वे शायद भूल गए कि उनके जहरीले विचार धीरे–धीरे कुत्सित कारनामों का रूप लेते जा रहे हैं। आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को इस अनहोनी का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। जमना–पार के इलाके की पुलिस खड़ी–खड़ी देखती रही और हथियारबंद गुंडे निहत्थे नौजवानों की पीट–पीटकर हत्या करते रहे। घरों, दुकानों और वाहनों को फूंका जाता रहा और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। यह किसी आदिवासी गांव की नहीं, दिल्ली की पुलिस है। सबसे अच्छे प्रशिक्षण, हथियार और सुविधाओं से लैस दिल्ली की पुलिस की यह अकर्मण्यता आश्चर्यजनक है।

यह वही पुलिस है, जिसने जामिया मिलिया के पुस्तकालय में जबर्दस्ती घुसकर छात्र–छात्राओं की पिटाई की और जिसने जेएनयू के छात्रों पर हमला करनेवाले गुंडों की अनदेखी की थी। इसका अर्थ क्या है? क्या यह नहीं कि हमारी पुलिस स्वायत्त नहीं है? वह अपने कायदों के मुताबिक सीधी कार्रवाई करने लिए स्वतंत्र नहीं है। वह नेताओं के आदेशों की या तो बाट जोहती रहती है या फिर उनके बिना कहे उनके रुझान को समझ लेती है। दिल्ली के इन दंगों में असफल हुई पुलिस स्वयं दंडनीय है। ठीक है कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दिल्ली–प्रवास के कारण अति व्यस्त रहे होंगे और दंगों पर ध्यान नहीं दे पाए लेकिन गृह मंत्रालय के दूसरे मंत्री और अफसर क्या कर रहे थे? दिल्ली के उप–राज्यपाल क्या कर रहे थे? दिल्ली में कानून–व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है।

सूडोकु नवताल-5259

मध्यम

			1					6
7		2		5				9
		4			2	7	5	
5	7				9		1	8
				6				
6	1		3				2	4
	5	1	9			8		
2				8		9		1
9					3			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5258 का हल

1	9	3	2	4	6	5	8	7
4	7	2	5	1	8	3	6	9
6	5	8	7	3	9	1	2	4
3	8	9	4	5	1	2	7	6
2	4	7	6	9	3	8	1	5
5	1	6	8	7	2	4	9	3
8	2	4	9	6	5	7	3	1
7	6	1	3	2	4	9	5	8
9	3	5	1	8	7	6	4	2

jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

घर-घर पहुंचकर भी सवालों में घिरी 'उज्ज्वला'

मोहन। सरकार ने मई 2016 में मुल्क के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी और तीन सालों में इस योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। स्वच्छ ईंधन के जरिए सरकार महिलाओं व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का लक्ष्य साधना चाहती है। जो बीमारियां खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले ईंधन यानी लकड़ी, कोयला, उपले आदि के जलने से होती हैं, उज्ज्वला योजना से उनमें कमी आने की उम्मीद की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कई चुनाव रैलियों व सार्वजनिक भाषणों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की भारी संख्या बताई जिससे उनकी व एनडीए सरकार की अच्छी छवि बनी। माना गया कि यह महिलाओं व बच्चों की फिक्र करने वाली सरकार है। मगर क्या एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना ही इस योजना को सफल साबित करने के लिए काफी है?